



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 427]
No. 427]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 26, 1995/कार्तिक 4, 1917
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 26, 1995/KARTIKA 4, 1917

कार्यिक, लोक शिक्षायत तथा पेशन मंत्रालय

कार्यिक और प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1995

सा. का. नि. 699(ब)।—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 § 1985 का 138 की धारा 35 की उप-धारा 128 के बण्ड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रवृत्त शाकियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के बेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के बेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1995 है।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के बेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 के नियम 8 में, उपनियम 128 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"128 उपनियम 11 के अधीन पेशन की संगणना सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए एक हजार चार सौ पचास रुपये प्रतिवर्ष की दर पर की जाएगी :

परन्तु इस नियम के अधीन केय पेशन तथा किसी अन्य पेशन एवं पेशन का संराशित भाग, यदि कोई हो, जो अधिकरण में पर धारण करते समय प्राप्त किया गया या जिसको प्राप्त करने का वह हकदार है, को जोखकर बनने वाली कुल राशि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित पेशन की अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी।"

[सं. ए-11014/13/95-प. अ.]
श्रीमती सरिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम विनांक 5 दिसम्बर, 1986 की सा. का. नि. 1253 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए एवं बाद में निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा संशोधित किए गए :—

- ॥१॥ सा. का. नि. 16 विनांक 10-1-1989
- ॥२॥ सा. का. नि. 1048 विनांक 13-12-1989
- ॥३॥ सा. का. नि. 743 विनांक 7-10-94

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 1995

G.S.R. 699(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with clause (c) of Sub-section (2) of Section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, in rule 8, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) Pension under sub-rule (1) shall be calculated at the rate of rupees one thousand four hundred and fifty per annum for each completed year of service :

Provided that the aggregate amount of pension payable under this rule together with the amount of any pension including commuted portion of pension, if any, drawn or entitled to be drawn while

holding office in the Tribunal shall not exceed the maximum amount of pension prescribed for a judge of the High Court."

[No. A. 11014/13/95-AT]
Smt. SARITA PRASAD, Lt. Secy.

Footnote :—The principal rules were published in the Gazette of India vide No. G.S.R 1253(E), dated the 5th December, 1986 and subsequently amended vide notification No. :

- (1) G.S.R. 16(E), dated 10-1-1989
- (2) G.S.R. 1048(E), dated 13-12-1989
- (3) G.S.R. 743(E), dated 7-10-1994

2538 GTE/95

